सरकार के उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, डेवलपमेंट कमिश्नर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दिल्ली को और उ० प्र० की सरकार और भूमि विकास बैंक को भी जानकारी दी है और मांग की है कि राजकोट में क्यू मार्क वाले डीजल इंजनों की मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक चालू रखे। इस के बारे में केन्द्रीय सरकार का उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश की सरकार और भूमि विकास बैंक को तुरन्त सूचना दे कि राजकोट (सौराष्ट्र) में बनते हुए डीजल आयल इजनो की क्वालिटी (क्यू) मार्क की मान्यता (रिकगनीशन) चालू रखें और जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर किसानो को सस्ता डीजल इजन देने की व्यवस्था अभी तक थी, इसे अमल में चालू रखें।

गुजरात सौराष्ट्र के फूलछाब, लोकमान्य, जनसत्ता, सदेश, गुजरात समाचार जयहिन्द वगैरह दैनिक अखबारो में अग्रलेख और समाचार के माध्यम से भी इसके लिए बहुत मागे की गई है।

डीजल आयल इजानियरिंग उद्योग को बचाने के लिए और क्यू क्वालिटी मार्क की मान्यता चालू रखने के लिए उद्योग मंत्रालय तुरन्त प्रबन्ध करे, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है।

(iii) Reported Hunger Strike by Labourers of Central Warehousing Corporation, New Delhi

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu): A large number of poor food handling labour of the Central Ware-Housing Corporation Tekh Khand Depot (Okhla, New Delhi) were working in the Depot since its inception under the Contract Labour System which expired on 31st October, 1977 as per the contract Labour (Regulation and Abolishing Act of 1970). The labourers are on relay hunger strike in front of the Central Warehousing Corporation from December 7th, 1977, with a further request to implement the direct payment system.

The wages of the labourers amounting to Rs. 50,000/- approximately, have not been paid besides restoration of all other rights, giving rise to a great unrest in the labour class and it can cause a deadlock besides other law and order situation and complications.

I appeal to the hon. Agriculture Minister and hon. Labour Minister to intervene and solve the problem with a further request that all other benefits to which the labourers are entitled may also be given to them.

A similar problem and situation flowing from the same set of factors is there at Jammu. These Ministers are requested to look into the matter as early as possible to avoid any grave situation which is apt to come out otherwise.

(iv) Reported Decision at the Chief Ministers' Conference about Abolition of Octroi

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मदसौर): मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन राज्यों द्वारा आक्ट्राय समाप्ति पर केन्द्र द्वारा जो वित्तीय सहायता दिये जाने की बात कही गई थी उसके न दिए जाने पर यह महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हू। राज्यो के मुख्य मत्रियो के सम्मेलन मे जो 18 जनवरी 1977 को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ था केन्द्र सरकार की ओर से परिवहन मत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जो राज्य आक्ट्राय समाप्त करेगे उन्हें इससे जो घाटा होगा उस घाटे को पचास प्रतिशत अनुदान दे कर पूरा किया जाएगा, या यह पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में उस घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र के इस आश्वासन के अनुसार आक्ट्राय समाप्त की गई और वित्तीय सहा-